

## वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की छत्तीसगढ़ की वन संरक्षण के लिये किये जा रहे कार्यों की सराहना

### चर्चा में क्यों?

12 अगस्त, 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से वन टरलियिन ट्री की प्रमुख निकोल सेवाड ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

### प्रमुख बडि

- गौरतलब है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वशिव स्तर पर वन टरलियिन ट्री योजना पर काम किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है।
- छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण को और कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, इस संबंध में वन टरलियिन ट्री कार्यक्रम की प्रमुख निकोल सेवाड के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परचिर्चा में शामिल हुए। इस परचिर्चा में भारत में वन टरलियिन ट्री कार्यक्रम की संचालक रतिविका भट्टाचार्य और भैरवी जानी ने कार्यक्रम के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी।
- निकोल सेवाड ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जंगल को अर्थव्यवस्था से जोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।
- परचिर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में साइंटिफिक तरीके से वनों के संरक्षण और भूजल स्रोत को रीचार्ज करने का काम किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के नाले 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक रीचार्ज हुए हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों के क्षेत्र में बेहतर काम किया जा रहा है, यदि इनके लिये लघु उद्योगों की स्थापना की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी लोग जागरूक होंगे।
- छत्तीसगढ़ में 42 फीसदी क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है और राज्य में 31 फीसदी आबादी आदिवासियों की है, जो प्रमुख रूप से वनों पर निर्भर हैं। इन्हें और समृद्ध बनाने के लिये छत्तीसगढ़ सरकार व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टों का वितरण कर रही है।
- मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को सुझाव देते हुए कहा कि मौसम के अनुसार ही यदि हम पौधों का रोपण करें तो वनों के वकिसति होने की संभावनाएँ ज़्यादा रहेंगी और ये तभी हो सकेगा, जब इनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि निरवा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने यही काम किया है। इससे नालों में पानी रीचार्ज हुआ है और पानी की पर्याप्त मात्रा होने की वजह से जंगल का दायरा बढ़ रहा है।